

बिहार गजट

अंसाधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

(सं0 पटना 173)

14 फाल्गुन 1946 (श0) पटना, बुधवार, 5 मार्च 2025

सं० बी01-3-04/2015-485 निर्वाचन विभाग

संकल्प

6 फरवरी 2025

विषय:— मतदान केन्द्र स्तरीय पदाधिकारी (बी०एल०ओ०) के पारिश्रमिक / मानदेय की राशि दिनांक 01.04.2025 से प्रति बी०एल०ओ० ₹6,000.00 (छः हजार रूपये) प्रति वर्ष से बढ़ाकर ₹9,000.00 (नौ हजार रूपये) प्रति वर्ष एवं पुनरीक्षण की अविध में बी०एल०ओ० द्वारा किये जाने वाले घरों के भ्रमण के लिए उन्हें अतिरिक्त ₹1,000.00 (एक हजार रूपये) प्रति वर्ष इस प्रकार ₹4,000.00 (चार हजार रूपये) प्रति वर्ष प्रति बी०एल०ओ० की दर से कुल ₹31,15,80,000 / —(इकतीस करोड़ पन्द्रह लाख अस्सी हजार रूपये) मात्र अतिरिक्त व्यय किये जाने के संबंध में।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 13ख(2) के अंतर्गत निर्वाचक सूची की तैयारी / पुनरीक्षण / निर्वाचन संचालन में सहयोग प्रदान करने हेतु मतदान केन्द्र स्तरीय पदाधिकारी (बी०एल०ओ०) का चयन सरकारी / अर्द्धसरकारी / स्थानीय निकायों के किमयों के बीच से किया जाता है। प्रत्येक बी०एल०ओ० निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के पर्यवेक्षण, अधीक्षण एवं नियंत्रण में एक मतदान केन्द्र के निर्वाचक नामावली को तैयार करने हेतु उत्तरदायी होते हैं।

2. भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली से प्राप्त निदेश एवं निर्वाचन विभाग का संकल्प संख्या 7662 दिनांक 06.11.2019 के आलोक में वर्त्तमान में प्रत्येक बी०एल0ओ० को ₹6000.00 (छः हजार रूपये) मात्र प्रति वर्ष की दर से पारिश्रमिक / मानदेय की राशि का भुगतान किया जा रहा है।

भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली का पत्रांक 23 / अनुदेश / 2015—ईआरएस दिनांक 08.07.2015 (परिशिष्ट—क) की कंडिका—7क के अनुसार प्रत्येक बी०एल0ओ0 को पारिश्रमिक / मानदेय के रूप में न्यूनतम ₹ 6000.00 (छः हजार रूपये) प्रति वर्ष दिये जाने का निदेश है। साथ ही कंडिका—7ख के अनुसार पुनरीक्षण की अवधि के दौरान बी०एल0ओ0 द्वारा किये जाने वाले घरों के भ्रमण के लिए उन्हें न्यूनतम ₹ 1000.00 (एक हजार रूपये) प्रति वर्ष दिये जाने का निदेश है।

3. बी०एल०ओ० के मानदेय का निर्धारण 5 वर्ष पूर्व अर्थात् वर्ष 2019 में किया गया था। पिछले दो वर्षों में BLO App लागू किये जाने के उपरांत अधिकतर कार्य बी०एल०ओ० द्वारा BLO App के माध्यम से ही संपादित किया जा

रहा है। BLO App के माध्यम से कार्य करने के क्रम में बीoएलoओo को मोबाईल एवं इंटरनेट की आवश्यकता होती है, जिसपर उन्हें अतिरिक्त व्यय वहन करना पड़ता है।

गत दो वर्षों में निर्वाचक सूची में नाम जोड़ने, विलोपित करने एवं संशोधित करने हेतु लगभग 1.53 करोड़ दावा / आपित प्राप्त किया गया, जिसमें से लगभग 97.60 लाख (63.79 प्रतिशत) दावा आपित बी०एल०ओ० द्वारा BLO APP के माध्यम से Digitize किया गया। साथ ही सभी प्राप्त दावा एवं आपित्त के निष्पादन के क्रम में बी०एल०ओ० द्वारा Field Verification भी किया गया। निर्वाचक सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के क्रम में Pre-revision Activities के तहत बी०एल०ओ० द्वारा घर—घर जाकर BLO App के माध्यम से गृह सत्यापन का कार्य किया जाता है।

- 4. कंडिका—3 में वर्णित तथ्यों के आलोक में मतदान केन्द्र स्तरीय पदाधिकारी (बीoएलoओo) के पारिश्रमिक / मानदेय की राशि दिनांक 01.04.2025 से प्रति बीoएलoओo ₹6,000.00 (छः हजार रूपये) प्रति वर्ष से बढ़ाकर ₹9,000.00 (नौ हजार रूपये) प्रति वर्ष एवं पुनरीक्षण की अविध में बीoएलoओo द्वारा किये जाने वाले घरों के भ्रमण के लिए उन्हें अतिरिक्त ₹1,000.00 (एक हजार रूपये) प्रति वर्ष इस प्रकार ₹4,000.00 (चार हजार रूपये) प्रति वर्ष प्रति बीoएलoओo की दर से कुल ₹31,15,80,000 / –(इकतीस करोड़ पन्द्रह लाख अस्सी हजार रूपये) मात्र अतिरिक्त व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की जाती।
- 5. बी०एल०ओ० मानदेय / पारिश्रमिक भुगतान पर हुए कुल व्यय का 50 प्रतिशत केन्द्र सरकार एवं 50 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। तद्नुसार बिहार सरकार द्वारा बी०एल०ओ० के मानदेय / पारिश्रमिक भुगतान पर वित्तीय वर्ष 2025—26 से 38,94,75,000 / (अड़तीस करोड़ चौरानवे लाख पचहत्तर हजार रूपये) मात्र की राशि का वहन प्रत्येक वर्ष किया जायेगा।
- 6. बी०एल०ओ० मानदेय / पारिश्रमिक की राशि बजट शीर्ष—2015—निर्वाचन—00—103—निर्वाचक नामावली तैयार करना और मुद्रण—0001—विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की सूची, विषय शीर्ष 0001.13.01 कार्यालय व्यय मांग संख्या—06 एवं विपत्र कोड संख्या—06—2015001030001 के अन्तर्गत विकलनीय होगा।
- 7. प्रस्ताव पर लोक वित्त समिति की दिनांक 31.01.2025 को आयोजित बैठक की कार्यवाही ज्ञापांक 287 / लो0वि0 दिनांक 31.01.2025 द्वारा अनुमोदन प्राप्त है।
- 8. कंडिका—4 में निहित प्रस्ताव पर राज्य मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही दिनांक—04.02.2025 के मद संo—135 द्वारा अनुमोदन प्राप्त है।

आदेशः— आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाये एवं इसकी प्रतिलिपि महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।

> बिहार-राज्यपाल के आदेश से, एच० आर० श्रीनिवास, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार –सह-प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । बिहार गजट (असाधारण) 173-571+10-डी0टी0पी0 । Website: http://egazette.bih.nic.in